

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *279
जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है।
20 फाल्गुन, 1947 (शक)

महाराष्ट्र में संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण संकुल 2.0 योजना

***279. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे :**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण संकुल (ईएमसी) 2.0 योजना के भाग के रूप में पुणे या इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में और विशेषकर पुणे के लिए उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटित और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और क्या इसमें किसी विलंब या धनराशि के कम उपयोग की सूचना मिली है;

(ग) क्या वित्तीय या प्रशासनिक बाधाओं से पुणे और महाराष्ट्र के अन्य भागों में ईएमसी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र, विशेषकर पुणे में मौजूदा या प्रस्तावित ईएमसी में बिजली, पानी, आंतरिक सड़कों और संभार-तंत्र संबंधी संपर्क मार्गों सहित मुख्य बुनियादी ढांचे की कमियों और चिह्नित की गई अन्य कमियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ईएमसी 2.0 योजना के अंतर्गत इन कमियों को दूर करने, विलंब की स्थिति से बचने और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट समयबद्ध सुधारात्मक उपायों, निगरानी और जवाबदेही तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

महाराष्ट्र में संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण संकुल 2.0 योजना के संबंध में दिनांक 11.03.2026 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *279 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

(क) से (ड) माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के लिए संपूर्ण विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रही है।

पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का काफी विस्तार हुआ है। इसे निम्नलिखित आँकड़ों से देखा जा सकता है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	~1.9 लाख करोड़	~12 लाख करोड़	6 गुना बढ़ा
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (रु.)	38 हजार करोड़	~3.3 लाख करोड़	8 गुना बढ़ा
मोबाइल विनिर्माण इकाइयां	2	300	150 गुना बढ़ा
मोबाइल फोनों का उत्पादन (रु.)	18 हजार करोड़	5.45 लाख करोड़	28 गुना बढ़ा
मोबाइल फोनों का निर्यात (रु.)	1,500 करोड़	2 लाख करोड़	127 गुना बढ़ा
आयातित मोबाइल फोन (इकाइयाँ)	कुल मांग का 75%	कुल मांग का 0.02%	

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0)

भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में संशोधित ईएमसी 2.0 योजना को अधिसूचित किया।

यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक और प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान करती है। इनमें तैयार औद्योगिक भूखंड और रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ)/प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं शामिल हैं।

ईएमसी 2.0 के तहत, 297 एकड़ क्षेत्र को शामिल करते हुए 492.85 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ रंजनगांव, पुणे में एक ग्रीनफील्ड ईएमसी को मंजूरी दी गई है। ईएमसी में परियोजना निवेश लगभग 2,000 करोड़ रुपये है और 5000 रोजगार सृजन होने का अनुमान है।

भारत सरकार ने 145.59 करोड़ रुपये का 70%स्वीकृत सहायता अनुदान (जीआईए) जारी किया है। परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, निधि का शेष 30% लक्ष्य प्राप्त करने और अन्य नियमों और शर्तों को प्राप्त करने पर जारी किया जाएगा।

परियोजना की भौतिक प्रगति एक उन्नत चरण में पहुंच गई है, जिसमें लगभग 80% बुनियादी ढांचा पूरा हो गया है। एंकर इकाइयों- मैसर्स आईएफबी रेफ्रिजरेशन लिमिटेड और मैसर्स स्टारियन एचके इंडिया ने उत्पादन शुरू कर दिया है।

इस योजना के अंतर्गत 67 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से पिंपरी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे में एक सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) भी अनुमोदित किया गया है। सीएफसी इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का समर्थन करने के लिए डिजाइन, प्रोटोटाइप, परीक्षण और माप के लिए साझा सुविधाएं प्रदान करेगा।

इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से तिमाही रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों और स्थल दौरों के माध्यम से की जाती है।

इसके अलावा, परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) और शासी परिषद (जीसी) समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करते हैं। इन समितियों में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं।
